



प्रेस विज्ञप्ति

25.11.2025

ईडी ने हैदराबाद में बैंक धोखाधड़ी से संबंधित पीएमएलए मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित की, आरोपी एल. श्रीनिवास गौड़ को न्यायालय ने 5 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

माननीय एमएसजे न्यायालय, नामपल्ली, हैदराबाद ने अपने 24.11.2025 के आदेश के तहत एल. श्रीनिवास गौड़ को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 सहपठित धारा 4 के तहत धन शोधन के अपराध का दोषी पाया और उन्हें 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। माननीय न्यायालय ने उन पर और उनकी फर्म मल्लिका इन बार एंड रेस्टोरेंट पर 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने धोखाधड़ी के एक मामले में जांच पूरी होने पर मल्लिका इन बार एंड रेस्टोरेंट और एल श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें मेसर्स मल्लिका इन रेस्टोरेंट एंड बार के मालिक एल श्रीनिवास गौड़ ने दस्तावेजों में जालसाजी और प्रतिरूपण करके धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त किया था। फेडरल बैंक के सामने अपनी मां का प्रतिरूपण करने के लिए एक जालसाज को प्रस्तुत किया गया था और उसकी मां की संपत्ति के शीर्षक विलेख दस्तावेजों में हेराफेरी करके और उनके जाली हस्ताक्षर करके ऋण प्राप्त किया गया था। ऋण को आवास ऋण के रूप में और रेस्तरां और बार के नवीनीकरण के लिए प्राप्त किया गया था, लेकिन इसे अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया गया और इसका दुरुपयोग किया गया, जिससे अपराध की आय उत्पन्न हुई और बैंक को 44.80 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

मुकदमे के दौरान, कई गवाहों से पूछताछ की गई और विभाग की दलीलें पूरी हुईं। हालाँकि, अभियुक्त जानबूझकर अदालत में पेश होने से बच रहा था, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने कई बार अभियुक्त के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए। कई प्रयासों के बावजूद, अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि वह अपने ज्ञात परिसर में मौजूद नहीं था। आगे के प्रयासों से पता चला कि उसने अपना निवास स्थान बदल लिया है। इसके बाद, इलेक्ट्रॉनिक और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर, नए पते की पहचान की गई, जिसकी जाँच की गई और न्यायालय के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि की गई। इसके बाद, एक सप्ताह की अवधि तक निगरानी रखी गई और नए पते पर उसकी उपस्थिति की पुष्टि हुई। 27 अक्टूबर 2025 के शुरुवाती घंटों में एक प्रयास किया गया, जब वह अंततः परिसर में पाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया। इस बीच, उसके द्वारा दायर लगातार जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए, क्योंकि अभियुक्त के पूर्ववृत्त पर विचार करते हुए, न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा करना उचित नहीं पाया। 24.11.2025 को, माननीय न्यायालय ने दोषसिद्धि आदेश पारित किया और अभियुक्त अभी भी न्यायिक हिरासत में है।